लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1 - 15 जनवरी 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक -57

"दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा।"
: स्वामी दयानंद सरस्वती

विभागों के विलय से मिलेगी सुशासन को गति

3

कृषि एवं बागवानी में निरंतर बढ़ते कदम

4

मेहमान परिंदों से गुलजार भिंडावास

6

मनोहर योजनाओं से बदली तस्वीर

मनोज प्रभाकर

लोगों का जीवन सहज व सरल करने के लिए पिछले आठ बरस में अनेक ऐसी योजनाएं आईं जिनकी वजह से राज्य की शासकीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था की तस्वीर ही बदल गई। यह सब संभव हुआ मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उनकी टीम की कड़ी मेहनत एवं ईमानदारी से। मुख्यमंत्री का शुरू से ही दृढ़संकल्प था कि सकारात्मक बदलाव के लिए वे कुछ भी करेंगे, कुछ भी सहेंगे तथा बिना किसी वाद से समझौता किए प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगे।

केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री ने अनेक ऐसी योजनाओं को जमीन पर उतारा जिनसे व्यवस्था का पूरा परिदृश्य बदलता चला गया। सबको साथ लेकर सबका विकास करने के लिए अंतोदय की भावना से कार्य किया जिसका परिणाम आज सबके सामने हैं। न कहीं अव्यवस्था है, न अफरातफरी का आलम और न कहीं असुरक्षा का भय। भेदभाव का तो सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की योजनाओं एवं नीतियों के चलते अनेक ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जिनकी वजह से मानो विपक्ष तर्कहीन हो गया है। जो अभूतपूर्व बदलाव हुआ वह है भाई भतीजावाद एवं क्षेत्रवाद मुक्त व्यवस्था।

प्रगति के पथ पर चलते हुए अनेक ऐसी योजनाएं उतारी गई हैं जो न केवल प्रदेश के लोगों को फायदा दे रही हैं, अन्य राज्यों के लिए भी नज़ीर बन गई हैं। दूसरे राज्यों ने इन योजनाओं को हाथों हाथ लिया है।

काबिलियत के आधार पर नौकरी, ऑन लाइन ट्रांसफर, खेल पुरस्कार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाल डोरा मुक्त अभियान के तहत स्वामित्व योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, परिवार उत्थान योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, श्रमिक कल्याण योजना, पेंशन योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और अब आयुष्मान भारत योजना के तहत चिरायु योजना।

काबिलियत के आधार पर नौकरी और ऑनलाइन ट्रांसफर नीति की वजह से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है बल्कि इससे राजनीति के मायने भी बदल गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल से पहले तक लोगों के मन में यह धारणा बन चुकी थी कि उपरोक्त दोनों कार्यों के लिए पर्ची और खर्ची दोनों का होना लाजिमी है। इनमें से कुछ नहीं होगा तो आजीविका की प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़ा जा सके गा।

पिछड़ने की वजह युवा अपनी नीयती मान बैठे थे। पढ़ना लिखना छोड़कर जुगाड़ की व्यवस्था में रहते थे। बड़े अफसर कैसे बनते हैं, आम परिवारों को तो इसका भान तक न था।

मनोहर सरकार बनने के बाद बदलाव आने लगा। एक एक करके सब पता लगने लगा। खबरें आने लगी कि फलां गरीब एवं मजदूर का बेटा या बेटी बड़ा अफसर बन गए हैं। पैसे व पहुंच वाले लोग सकते में थे कि यह सब हो क्या रहा है? एक के बाद एक परिणाम पढ़ने लिखने वाले युवाओं के पक्ष में आने लगे तो लोगों की सोच बदलती चली गई। नतीजा यह है कि आज युवा व उनके अभिभावक जुगाड़ की बात नहीं करते परीक्षा के सलेबस पर चर्चा करते हैं।

ट्रांसफर नीति ऐसी आई कि बरसों से एक ही स्थान पर चौधर जमाते आ रहे कर्मचारी एवं अधिकारी बदलते चले गए। स्कूलों में पढ़ाई होने लगी और सरकारी कार्यालयों में काम होने लगे तो लोगों को सुकून मिला और धारणा बदलती चली गई।

खेल पुरस्कार योजनाओं की वजह से तो म्हारे छोरे और छोरियां ने

पूरे विश्व में डंका बजा दिया है। न केवल वैश्विक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी युवाओं की मेहनत और राज्य सरकार की खेल नीति प्रेरणा का विषय बन गई हैं। दूसरे प्रदेशों से इन बारे में जानकारी लेने के लिए अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां की खेल नीति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परिवार पहचान पत्र योजना, स्वामित्व योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना व अन्य योजनाओं की खूब प्रशंसा कर चुके हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ईमानदारी एवं कड़ी मेहनत की जमकर तारीफ की है। गृह मंत्री अमित शाह तो यहां तक कह चुके हैं कि हरियाणा को ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री पहली बार मिला है।

उक्त नेताओं की कथनी को लेकर कोई अतिश्योक्ति भी नहीं होनी चाहिए। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आराम किया हो, अवकाश तो कभी लिया ही नहीं। कोरोना काल में उन्होंने जिस शिद्दत के साथ लोगों की सेवा की वह अद्भूत एवं अविस्मरणीय रही।

मुख्यमंत्री की परिवार उत्थान योजना जिसके तहत गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, भी दूसरे प्रदेशों में लोकप्रिय हो रही है। हरियाणा में अपर्याप्त आय वालों को इस श्रेणी में रखा गया है।

गांव व शहरी क्षेत्रों में लागू की गई स्वामीत्व योजना ने बरसों पुराने विवादों को सुलझाने का काम किया है। इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिली है। बहुत से केस तो अदालतों में लंबित थे उनका निदान हुआ है।

मेरा पानी मेरी विरासत के तहत करीब 20 हजार तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है तथा जल संरक्षण के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों को परंपरागत फसलों से अलग फसल उगाने पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

गरीब परिवारों को चिकित्सा खर्च के दंश से उबारने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की गई है। चिरायु योजना के तहत करीब 16 लाख और परिवारों को इस योजना में शामिल गया है जिनका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अनेक परिवारों के लिए ये योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं।

विभागों को मिली शाबाशी

सुशासन की परिपाटी स्थापित करने में राजकीय विभागों का विशेष योगदान रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए विभागों को सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। सुशासन दिवस पर विभिन्न विभागों को 7 राज्य स्तरीय और 15 जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिए गए। इन पुरस्कारों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जैसे परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, चिरायु हरियाणा योजना, ऑटो अपील सिस्टम सहित कई प्रोजेक्ट शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस पर नवर्वाचित पंचायती जन प्रतिनिधियों से संवाद किया और नववर्ष के अवसर पर सुशासन पर चलने का आह्वान किया।

परिवार पहचान पत्र योजना के तहत 16 दिसंबर तक 2.8 5 करोड़ से अधिक नागरिकों और 71.89 लाख से अधिक परिवारों ने पीपीपी में अपना डाटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पीपीपी के साथ जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत तीन चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 आवेदन स्वीकृत किए गए। 35,414 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं।1901 लाभार्थियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां दी गई।

ऑटो अपील सिस्टम (आस)

ऑटो अपील सिस्टम प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण, द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण, और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपीलें की गई, जिनमें से 2,76,238 अपीलों का समाधान किया गया है। इस प्रणाली के लॉन्च होने के एक साल के भीतर ही ऐसी लंबित अपीलों की संख्या में भारी कमी आई है।

भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार सख्त

हरियाणा सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत लंबित 30 अलग-अलग मामलों में विभागों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के विरुद्ध चल रहे अक्टूबर माह तक के मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही एक पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिस पर विभाग विजिलेंस मामलों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां जैसे, एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर), जांच रिपोर्ट, अभियोजन की मंजूरी इत्यादि अपलोड कर सकेंगे।

कोरोना से घबराएं नहीं, एहतियात बरतें

कोरोना एक बार फिर चर्चा में है। राज्य सरकार का मानना है कि उनके यहां फिलहाल ऐसी कोई परेशानी नहीं है लेकिन उसको लेकर सावधान रहने की जरुरत है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि यदि कोरोना से संबंधित केंद्र की कोई भी गाइडलाइन आएगी तो उसको प्रदेश में पूरी तरह से लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा हालांकि उनके यहां ऐसे हालात नहीं हैं लेकिन उसके लिए सभी को सावधान रहने की जरुरत है। कोरोना की पिछली लहरों से उन्होंने अनुभव ले लिए थे, आज वे उस आशंकित लड़ाई के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि उनके पास वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है, पहले ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा में दिक्क त आई थी लेकिन अब 50 बिस्तर से ऊपर के सभी अस्पतालों में पीएसए प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार, दवाइयों का भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है

उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को किसी प्रकार का भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, अलबत्ता कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं उनका अमल करें। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वह सबके लिए आवश्यक है, वह लोगों को स्वयं से पालन करना चाहिए।

कैंसर पीड़ितों को पेंशन

हरियाणा सरकार ने स्टेज- 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रूपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 68 करोड़ 42 लाख रूपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। बतादें मुख्यमंत्री ने मई, 2022 को जब उनसे कैंसर पीड़ितों के परिवार मिले थे तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है परंतु वे डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन वे कैंसर पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। यह सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए तक है।

संपादकीय

नववर्ष के नए संकल्प

वर्ष 2014 से चली परम्परा को जारी रखते हुए इस बार भी राष्ट्रनायक एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन-दिवस के रूप में राज्य स्तर पर मनाया गया और मुख्यमंत्री के 'अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार' के विज़न को मूर्त रूप देने हेतु इस सुशासन दिवस पर विभिन्न विभागों को सात राज्य स्तरीय और 17 जिला स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिए। 25 दिसंबर, 2022 को सुशासन दिवस पर पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा यह पुरस्कार वितरित किए गए। इन पुरस्कारों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं और परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, चिरायु हरियाणा योजना, ऑटो अपील सिस्टम (आस) सहित कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। सुशासन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और राज्य सरकार द्वारा लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक-केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिए गए हैं। ये सुधार प्रगतिशील राज्यों में हरियाणा को अग्रणी बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 26 अक्तूबर, 2014 को सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो माह पश्चात ही 25 दिसम्बर, 2014 से ही, पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हरियाणा में पहली बार सुशासन की अवधारणा लागू की थी। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एक नया संकल्प लेते हैं और वर्ष भर उस को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय व प्रशासनिक सचिव स्तर के अधिकारियों का विशेष फोक्स रहता है।

इस अवसर पर 'वर्चुअल माध्यम' से मुख्यमंत्री सभी जिलों से भी जुड़े और नवघोषित-संकल्पों पर अमल के मामले में सामान्य जन से भी संवाद स्थापित किया। ऐसे 'जन संवाद कार्यक्रम' रोहतक, सिरसा, करनाल, कुरुक्षेत्र, पचकूला व सोनीपत जिलों में मुख्यमंत्री स्वयं जाकर सम्पन्न कर चुके हैं। ये सब योजनाएं प्रदेश की जनता को एक सार्थक दिशा प्रदान करेंगी।

यह सक्रियता निश्चित रूप से नव वर्ष 2023 में और भी अधिक गति लेगी। संवाद के सभी पाठकों को नववर्ष की शुभ कामनाएं।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

हिंदी में भी मिलेंगे न्यायालयों के आदेश

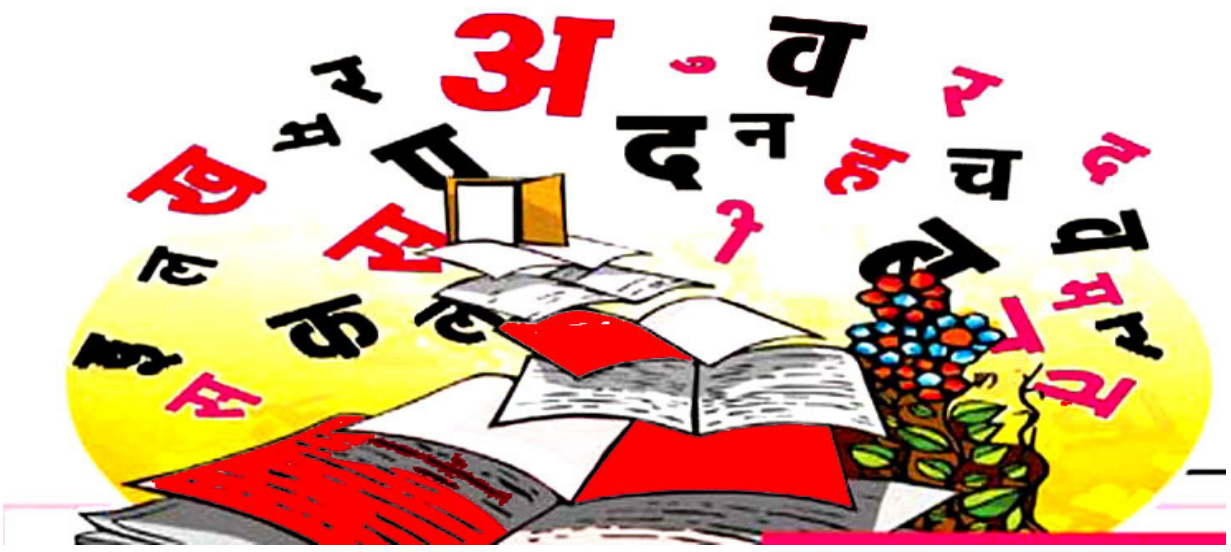

हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों में हिंदी भाषा के उपयोग के संबंध में हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में हरियाणा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजनों के उपयोग के लिए जारी अधिसूचना को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनुमोदित कर दिया है जो एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।

सरकार ने जनमानस की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है। दैनिक जीवन में लोग हिंदी भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी भाषा अधिकाधिक प्रचार प्रसार आवश्यक है। लोकतंत्र में न्याय का उद्देश्य यह है कि वादी को अपनी भाषा में जल्दी न्याय मिलना चाहिए और कार्यवाही के दौरान वह अवाक न रहे। इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

1969 में माना था अधिकारिक भाषा

हरियाणा राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के तहत हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। तब से, हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जा रहा है। पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3ए और 3बी जोड़े गए थे, कि सभी सिविल न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ थे और सभी राजस्व न्यायालय और अधिकरण, में काम पंजाबी में किए जाएंगे।

इसी तरह के संशोधन को हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में भी लाया गया है, जो कि सभी न्यायालयों में उस कार्य को प्रदान करने के लिए, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और राज्य सरकार द्वारा गठित सभी न्यायाधिकरणों द्वारा हिंदी में देवनागरी लिपि में काम किया जाएगा और हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में धारा 3ए को जोड़ा गया है, जिसके तहत पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल अदालतों और आपराधिक न्यायालयों में, सभी राजस्व अदालतें और रेंट ट्रिब्यूनलों या किसी अन्य अदालत या राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण, ऐसी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही, कोई भी निर्णय, डिक्री या आदेश पारित, हिंदी में भी होगा।

-संवाद ब्यूरो

औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर 'एनसीआर'

देश-विदेश के बाद दिल्ली के व्यापारियों का भी हरियाणा की ओर रुख

हरियाणा को पिछले आठ वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर किया है। एक ओर जहां प्रदेश में 18,422 करोड़ रुपए के निवेश से 1,59,622 उद्योग लगे हैं वहीं इनसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार उपलब्ध हुए हैं। सरकार ने सड़क, रेल, हवाई आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष फोकस देकर कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के साथ- साथ कई नए औद्योगिक शहर विकसित करने की कवायद भी तेज़ की है।

भौगौलिक दृष्टि से हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद रहा है। कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के बाद 5,618 करोड़ रुपए की लागत से पलवल-सोनीपत डबल लाइन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य आरंभ होने से दिल्ली के व्यापारियों ने भी हरियाणा का रुख किया है। केएमपी के साथ-साथ पंचग्राम अवधारणा के साथ पांच नए शहर बसाने का खाका तैयार करने का कार्य जारी है जो वर्ष 2041 की संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इन नए शहरों के बसने से दिल्ली में न केवल जनसंख्या घनत्व कम होगा, बल्कि दिल्ली के उद्योग भी इन शहरों में शिफ्ट करेंगे। हरियाणा में पिछले आठ वर्षों में सड़क, रेल व हवाई तंत्र के आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष फोकस किया गया है। आज हरियाणा के हर जिले से कम से कम तीन या चार राष्ट्रीय राज़मार्ग गुजरते हैं। उद्योग के लिए सड़क, रेल व हवाई तंत्र सुदृढ़ होना आवश्यक है जिस पर हरियाणा पिछले आठ वर्षों में खरा उतरा है। हिसार हवाई अड्डे को 'उड़ान योजना' के तहत विकसित किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे एविएशन हब व एमआरओ के रूप में तैयार किया जायेगा।

निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं

पिछले आठ वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह से हरियाणा के विकास का पहिया तेज़ गति से घुमाया है उसके फलस्वरूप हरियाणा विकासशील प्रदेशों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और कई क्षेत्रों में अन्य राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा नई'हरियाणा उद्यम एवं रोज़गार नीति-2020' लागू की है जिसका लक्ष्य पांच लाख नये रोज़गार के अवसर सर्जित करना और एक लाख करोड़ रुपए का निवेश तथा दो लाख करोड़ रुपए के निर्यात का है। इसके अलावा वेयरहाऊस और लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल्स तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी क्षेत्रीय नीतियां बनाई गई। हरियाणा के औद्योगिक विकास की प्रगति का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के निर्यात ग्राफ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में हरियाणा का निर्यात 69 हजार करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर 2 लाख 17 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया। इसमें मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट शामिल हैं। अब तो राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 'हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति - 2022' भी अधिसूचित कर दी है।

कई मेगा प्रोजेक्ट्स

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निरंतर बैठकें कर उन्हें प्रदेश में मेगा प्रोजेक्टों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उनके यह प्रयास धरातल पर उतरे भी हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा ने लगभग 67 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के साथ 20,971 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। फ्लिपकार्ट ग्रुप पाटली हाजीपुर, मानेसर में 140 एकड़ जमीन पर एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस परियोजना में 1,389 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है जिससे लगभग 16 हजार से अधिक रोज़गार के अवसर मुहैया होंगे। इसके अलावा, सोनीपत में मारुति सुजुकी 18,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आईएमटी खरखोदा में 800 एकड़ भूमि पर अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित कर रही है। राज्य सरकार ने आईएमटी खरखोदा में मेसर्स सुजुकी मोटरसाइकिल को 100 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए के निवेश होने की संभावना है। पानीपत में मैसर्स आदित्य बिड़ला समूह को पेंट निर्माण प्लांट के लिए औद्योगिक एस्टेट में 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से हरियाणा राज्य में 1,140 करोड़ रुपए के निवेश हो रहा है। गुरुग्राम में मेसर्स एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को आईएमटी सोहना में 178 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से राज्य में 7,083 करोड़ रुपए का निवेश आएगा जिससे 7,000 से अधिक रोज़गार के अवसरों का सृजन होगा। इतना ही नहीं, कई बड़े निवेशक जैसे एनरिच एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेजेज, आरती ग्रीन टेक हरियाणा में कारोबार करने के प्रति उत्सुक हैं।

मसाला मंडी की संभावनाएं

हरियाणा में केएमपी चालू होने के बाद इसके दोनों ओर पंचग्राम की नई अवधारणा के तहत पांच नए शहर विकसित करने की एक महत्वकांक्षी योजना पर कार्य चल रहा है। इस परियोजना से दिल्ली के व्यापारी हरियाणा में अपना व्यवसाय बढ़ाने की संभावना तलाशने लगे हैं जिसमें मुख्य रूप से होलसेल मार्केट, आजादपुर सब्जी मंडी व मसाला कारोबार से जुड़े व्यापारी शामिल हैं।

-मनोज प्रभाकर

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

सरकारी विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी अगर रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत निम्न फोन पर करें- 1800182022, 1064, वाट्सऐप- 9417891064 ई मेल. svp@hry.nic.in, dgsvp-hry@nic.in, svbhqrs@gmail.com

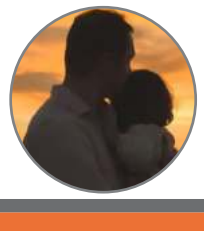

हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 के तहत अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी मिलेगी। यह नियम हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2022 कहे जाएंगे।

सरकार ने रखा आम जन का ख़्याल

संगीता शर्मा

नया साल हरियाणावासियों के लिए नई सौगात लेकर आएगा। जहां एक ओर हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023 'अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज' के रूप में मनाया जाएगा, वहीं आमजन के हितों को ध्यान में रखते नई योजनाओं को नया रूप दिया जा रहा है। हरियाणा की गठबंधन सरकार ने गांवों व शहरों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई कोर कसर छोड़ी जाएगी। सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार की है कि अब लोगों को घर बैठे ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। अब बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि एक जनवरी 2023 से एक लाख 80 हजार रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों की वेरीफाई आय के आधार पर बीपीएल कार्ड अपने आप ही बन जाएंगे।

ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विज़न और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट घोषणा से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार ने प्रदेशभर के अविकसित ब्लॉकों में रहने वाले अंत्योदय परिवारों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए 'ब्लॉक परिवर्तन कार्यक्रम' (बीपीपी) शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत, प्रत्येक जिले से एक अविकसित ब्लॉक की पहचान की जाएगी और गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा एवं शासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल समानता और अधिकारिता, जल व स्वच्छता, ऊर्जा प्रबंधन, सामाजिक विकास, कृषि और सिंचाई सहित प्रमुख बिंदुओं पर काम शुरू किया जाएगा।

हाऊसिंग फॉर ऑल

हरियाणा में जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप 'हाऊसिंग फॉर ऑल' विभाग एक मज़बूत फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक ऐसा न हो, जिसके सिर पर छत न हो। इसलिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द से जल्द घर बनाकर दिये जाएं। इन-सिटू स्लम रिडेवलपमेंट घटक के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला या अन्य जिलों में भी स्लम एरिया को चिह्नित कर एक योजना तैयार की जाएगी और इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए शीघ्र-अतिशीघ्र केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

चिरायु योजना से जरूरतमंदों का ईलाज

'चिरायु हरियाणा योजना' के तहत प्रदेश के ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने की शुरुआत की है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है। इस योजना में शामिल किए जाने वाले इन परिवारों के ईलाज का पांच लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पहले हरियाणा में 15 लाख 51,798 परिवार आयुष्मान भारत योजना में कवर हो रहे थे। लेकिन अब हमने राज्य सरकार के खर्च पर योजना का दायरा बढ़ाया है। इससे प्रदेश में अब 28 लाख 89,036 परिवार कवर हो रहे हैं।

सॉफ्टवेयर से तैयार होगी फ़र्द

प्रदेश में जमीन की फ़र्द तैयार करने के लिए नया सॉफ्टवेयर लिया गया है और इसके माध्यम से किसानों को अपनी ज़मीन की फ़र्द लेने के लिए पटवारखानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो फ़र्द यानी जमाबंदी निकाली जाएगी, उस पर क्यू आर कोड अंकित होगा। क्यू आर कोड अंकित होने के कारण ही इस फर्द को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार से खरीदा है और इस सॉफ्टवेयर से जो जमाबंदी निकाली जाएगी, उससे किसान ऋण भी ले सकेंगे और पटवारी से हस्ताक्षर करवाने की भी जरूरत नहीं होगी।

भ्रष्टाचार पर लगाम

प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस नीति अपनाते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार मामलों की समीक्षा हेतु हाई पॉवर कमेटी का गठन किया है। राज्य सरकार विजिलेंस विभाग को मज़बूत कर रही है। विभागों में मामलों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सेवानिवृत आईएएस अधिकारी, केंद्रीय और स्टेट सर्विस में रहे अधिकारियों को लगाया जाएगा। इसके लिए मापदंड तय कर लिये गए हैं और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है, जो सीवीओ के लिए अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट करेगी। इसके अलावा, डिप्टी सीवीओ भी लगाए जाएंगे।

सात और जिलों में बनाए जाएंगे हेलीपैड

प्रदेश के लगभग हर जिला में हेलीपैड बनाए जाएं ताकि इमरजेंसी तथा अन्य आवश्यकता अनुसार हेलीकॉप्टर की लैंडिग करवाई जा सके। हिसार,अंबाला, सिरसा, करनाल,भिवानी, नारनौल, पंचकूला जिला के पिंजौर समेत राज्य के कई स्थानों पर हवाई पट्टियां पहले से बनी हुई हैं, शेष जिलों की आपसी-दूरी को ध्यान में रख कर जींद, झज्जर, कैथल, सोनीपत, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र व रोहतक जिलों में चिन्हित स्थानों पर हेलीपैड बनाए जाने के लिए उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रथम चरण में राज्य में सात और जिलों में हेलीपैड बनाए जाएंगे ताकि इमरजेंसी के समय भी ये हेलीपैड प्रयोग किए जा सकें। उन्होंने हेलीपैड सिक्योरिटी व लाइटनिंग आदि की व्यवस्था करने बारे भी निर्देश दिए।

विभागों के विलय से मिलेगी सुशासन को गति

मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला

हरियाणा में विभिन्न विभागों के कामकाज में बेहतर तालमेल लाने और कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक ही प्रकार की कार्य प्रकृति वाले कुछ विभागों का विलय एवं पुनर्गठन करने का निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। निदेशालय, यूटिलिटीज और प्राधिकरण पहले की तरह काम करते रहेंगे। वरिष्ठता के कानूनी मुद्दों से बचने के लिए वर्तमान में किसी भी कर्मचारी काडर का विलय नहीं किया जाएगा। इस आशय के एक प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को विद्युत विभाग के साथ विलय किया गया है और विभाग का नाम बदलकर ऊर्जा विभाग किया गया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय विभाग अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का विलय करने के बाद इनका नाम इनका बदलकर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय विभाग किया गया है।

उच्चतर शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का विलय एक सिंगल विभाग में किया गया है। इस विभाग का नाम उच्चत्तर शिक्षा विभाग किया गया है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का पर्यटन विभाग में विलय किया गया है। इस विभाग का नाम बदलकर हैरिटेज और पर्यटन विभाग किया गया है। वन एवं वन्य जीव विभाग तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का विलय कर इसका बदलकर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग किया गया है।

कला एवं संस्कृति विभाग का विलय सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के साथ किया गया है और इसका नाम बदलकर सूचना, जनसम्पर्क , भाषा एवं संस्कृति विभाग किया गया है।

खेल विभाग से केवल युवा मामलों के घटक को निकाल कर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग और रोज़गार विभाग के साथ विलय किया गया है। विलय करने के बाद विभाग का नाम युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमशीलता विभाग किया गया है। नया विभाग कौशल, प्रशिक्षण व कौशल शिक्षा सहित युवा मामलों को व्यापक रूप से देखेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भंग करने और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तथा निजी आईटी को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के दायरे में लाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वर्तमान कार्यों को विभिन्न मौजूदा विभागों को आवंटित किया गया है। इसके तहत, आईटी उद्योग से संबंधित कार्य/विषयों को उद्योग विभाग को पुनः आवंटित किया गया है। ई-गवर्नेंस से जुड़े कार्य/विषयों और परियोजनाओं/शासन में आईटी के उपयोग को नागरिक संसाधन सूचना विभाग को फिर से आवंटित किया जाना जाएगा। हारट्रोन एक इकाई के रूप में रहेगा और उद्योग विभाग को आवंटित किया जाना चाहिए।

निगरानी एवं समन्वय विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग को एक मौजूदा विभाग जोकि सामान्य प्रशासन विभाग है, में विलय कर दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, सीईटी के संबंध में नीतियां, जो पहले मानव संसाधन विभाग को हस्तांतरित किए गए थे, उन्हें वापस ले लिया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से वित्त विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

चकबंदी विभाग तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का विलय कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग किया गया है। इसके अलावा, फायर सर्विस, फायर सेफ्टी निदेशालय को शहरी स्थानीय निकायों से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित किया जाएगा।

- संवाद ब्यूरो

आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 6 साल तक बच्चों, वर्कर्स तथा हैल्पर्स की उपस्थिति प्रतिदिन ऑनलाइन लगेगी। सीएम की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबाइल उपलब्ध करवाने के निर्देश हुए ताकि केंद्र के डाटा को अपडेट रखा जा सके।

हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज पर चल रही पालिकाओं की व्यवसायिक भूमि की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने के लिए बनाई गई स्वामित्व योजना को अन्य विभागों द्वारा भी अपनाया जाएगा।

कृषि एवं बागवानी में निरंतर बढ़ते कदम

हरियाणा ने जीता गोल्डन अवार्ड

हरियाणा द्वारा कृषि और बागवानी क्षेत्र में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। दोनों विभागों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम में अपनी-अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है। यह अवार्ड हरियाणा की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा एवं बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी ने नई दिल्ली में प्राप्त किया।

33 एकीकृत पैक-हाउस स्थापित

राष्ट्रीय पूल में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाले हरियाणा प्रदेश ने बागवानी की दिशा में विविधिकरण और कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। हरियाणा ने लगभग 400 बागवानी फसल समूहों की मैपिंग की है और 700 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है। क्लस्टर में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मज़बूत करने के लिए राज्य ने एफपीओ के माध्यम से ऑन-फार्म इंटीग्रेटेड पैक-हाउस की स्थापना के लिए 510.35 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक महत्वाकांक्षी योजना-'फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी)' शुरू की है। प्रदेश में अब तक 33 एकीकृत पैक-हाउस स्थापित किए जा चुके हैं और 35 प्रगति पर हैं।

चालू वित्त वर्ष के अंत तक ऐसे कुल 100 एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, किसानों और कृषि उपज के लिए अंतिम मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र की 37 कंपनियों ने कृषि-व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बाय-बैक तंत्र के साथ एफपीओ के उत्पादन के व्यापार और विपणन के लिए 34 एफपीओ के साथ 54 समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं। 10 महीने की छोटी अवधि में 13,400 मीट्रिक टन बागवानी वस्तुओं का व्यापार का मूल्य 14 करोड़ रुपए से अधिक है, जो भविष्य में 200 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है।

'हर खेत-स्वस्थ खेत' अभियान

हरियाणा किसानों को बाज़ार और उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए राज्य में बागवानी आपूर्ति श्रृंखला का पूर्ण आधुनिकीकरण हासिल करना है। 'हर खेत-स्वस्थ खेत' अभियान के तहत तीन-चार वर्षों में लगभग 75 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र कर उनका परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक एकड़ के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) किसानों को वितरित किए जाएंगे। मृदा परीक्षण के बारे में लोगों की भागीदारी और ज़ागरूकता बढ़ाने के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण का कार्य किसान सहायकों, (स्थानीय ग्रामीणों) और 'अर्न व्हाइल यू लर्न' कार्यक्रम के तहत सरकारी कॉलेजों, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के विज्ञान छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

-संवाद ब्यूरो

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

हरियाणा राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक विस्तृत नेटवर्क है जहां किसानों की मिट्टी परीक्षण के लिए आसान पहुंच है। 20-25 किलोमीटर की परिधि में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की उपलब्धता है। 2020-21 से पहले विभाग 35 स्थैतिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, जो सालाना 7.4 लाख मिट्टी के नमूनों का परीक्षण कर सकती थीं। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान विभाग ने 60 नए एसटीएल (13 स्थिर + 47 मिनी) बनाए, अब विभाग के पास कुल 95 (48 स्थिर + 47 मिनी) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जो सालाना 30 लाख मिट्टी के नमूनों का परीक्षण कर सकती हैं।

सरसों की खेती का रख-रखाव

हिसार, भिवानी, सिरसा, महेन्द्रगढ, रेवाड़ी तथा झज्जर में इसकी मुख्यत काश्त की जाती है। फसल की नियमित देखभाल बहुत जरुरी है। देखरेख के अभाव में या प्राकृतिक दृष्टि से कई बार फसल रोग ग्रस्त होने लगती है। बचाव के लिए कुछ आवश्क बातें।

चितकबरा कीड़ाः

इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं जिसके कारण इसे धोलिया नामक कीट भी कहा जाता है। अधिक आक्रमण की स्थिति में पूरा पौधा सूख जाता है। इसका प्रकोप फसल की उगती हुई अवस्था एवं कटाई के समय होता है।

इस कीट की रोकथाम के लिए फसल उगने के समय 200 मि.ली. मैलाथियान (सायथियान, मैलामार, मैल्टाफ) 50 ई.सी. को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिडकाव करें। यदि आवश्यकता हो तो फसल कटाई के समय 400 मि.ली. मैलाथियान 50 ई.सी. को 400 लीटर पानी में मिलाकर मार्च में भी छिड़काव करें।

सरसों का चेपा (अल/माह):

हल्के पीले-हरे रंग का यह कीट छोटे-छोटे समूहों में रहकर पौधे के विभिन्न भागों से विशेषकर कलियों, फलों, फलियों व फूलों की टहनियों पर रहकर रस चूसता है। इसका अधिक आक्रमण दिसम्बर के अन्तिम और जनवरी के प्रथम पखवाड़े में होता है जब औसत तापमान 10-20 डिग्री सैं. एवं 75 प्रतिशत आर्द्रता हो। रस चूसे जाने से पौधे की बढ़वार रूक जाती है, फलियां कम लगती हैं और उनमें दाने की संख्या कम होती है।

सफेद रतुआः

तने तथा पत्तियों पर सफेद अथवा पीले क्रीम रंग की कील से प्रकट होते हैं। तने व फूल बेढंगें आकार के हो जाते हैं। यह ज्यादा पछेती फसल में अधिक होता है।

आल्टरनेरिया ब्लाईटः

पौधे के पत्तों, तनों तथा फलियों पर गोल, भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। बाद में ये धब्बे काले रंग के हो जाते हैं तथा इनमें गोल छल्ले से नजर आते हैं।

आल्टरनेरिया ब्लाईट और सफेद रतुआ की रोकथाम के लिए पहली फसल के बचे हुए रोगग्रस्त अवशेषों को नष्ट करें। बीमारी के लक्षण नजर आते ही 600 ग्रा. मेन्कोजैब (डाइथेन या इन्डोफिल एम-45) को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अन्तर पर 3-4 बार छिड़काव करें।

तना गलनः

तनों पर लंबे आकार के भूरे जलसिक्त धब्बे बनते हैं, जिन पर बाद में सफेद फफूंद की तह बन जाती है। ये लक्षण पत्तों तथा टहनियों पर भी नजर आ सकते हैं। फूल निकलने या फलियां बनने के समय आक्रमण होने पर तने टूट जाते हैं और पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। ऐसे पौधों के तनो पर या तनों के भीतर काले रंग के पिंड (स्कलरोशिया) बनते है।

इसके बचाव के लिए बिजाई से पहले 2 ग्राम कारबेन्डाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। जिन क्षेत्रों में तना गलन रोग का प्रकोप हर साल होता है वहां बिजाई के 45-50 दिन तथा 65-70 दिन के बाद कारबेन्डाजिम का 0.1 प्रतिशत की दर से दो छिड़काव करें।

मरगोजा परजीवी खरपतवार

मरगोजा पूर्णत परजीवी खरपतवार है और राया की जड़ो से ही पूरी खूराक व पानी लेता है। राया की जड़े जमाव के 5 से 7 दिन बाद ओरबैनकोल व एलिकटरोल रसायन छोड़ती है। जिससे राया की जड़ो के पास पड़े मरगोजा के बीज उतेजित होकर उगने शुरू हो जाते है। इसके नियंत्रण के लिये राऊंडअप/ग्लोईफोसेट 41 प्रतिशत एस.एल. की 25 मिली. मात्रा प्रति ऐकड़ बिजाई के 25-30 दिन के बाद व 50 मिली. मात्रा प्रति एकड़ बिजाई के 50 दिन बाद 125-130 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

राम अवतार, कृषि विश्वविधालय, हिसार

सोनीपत के गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी हार्टिकल्चर मार्केट बनने जा रही है। इसके बनने से किसान अपने उत्पाद को एक स्थान पर बेचकर अधिक लाभ कमा सकेंगे।

हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार 13 से 29 जनवरी तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हरियाणा के खिलाड़ियों में विशेष उत्साह एवं जुनून देखा जा रहा है।

सेहत के लिए फायदेमंद है मोटे अनाज का सेवन

'अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज' के रूप में मनाया जाएगा वर्ष 2023

संगीता शर्मा

वर्तमान समय की भागदौड़ व व्यस्तता भरे जीवन में हर कोई व्यक्ति बीमारी व तनाव से ग्रस्त है और ऐसे में मोटे अनाज को आहार में खाने से स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। मोटे अनाज को जहां कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में उगाकर किसानों को फ़ायदा होता है, वहीं ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अति उत्तम हैं। हमारे बड़े-बुजुर्ग ने पोषक अनाजों के ज़रिए ही एक सेहतमंद जीवन को लंबी आयु तक जीया है। आज हमें नई पीढ़ी को इनकी अहमियत समझाने और इनके प्रति ज़ागरूक करने की आवश्यकता है। इसी मकसद से भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष' के रूप में घोषित किया है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा में मोटे अनाज (मिलेट्स) की पौष्टिकता के महत्व के प्रति लोगों को ज़ागरूक करने व किसानों को प्रशिक्षण देने के सार्थक कार्य किए जाएंगे। हरियाणा ऐसा राज्य है जो नवाचार करने में कभी पीछे नहीं हटता।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी.दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में प्रदेश एक कदम आगे बढ़कर कार्य करेगा। हरियाणा में मुख्य रूप से बाजरा फसल को ही मोटे अनाज के रूप में उगाया जाता है। आजीविका में बाजरा/ज्वार पोषक अनाज से अपार संभावनाएं हैं। यह गेहूं और चावल की तुलना में कम कार्बन अपशिष्ट के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है।

मिलेट्स से बिमारियों का ईलाज़

मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉ खादर अली का कहना है कि मोटे अनाज (मिलेट्स) की पौष्टिकता के महत्व के बारे में लोगों को ज़ागरूक करना बहुत ज़रूरी है। पोषक-अनाज के सेवन से काफ़ी बिमारियां खत्म हो जाती है। उन्होंने बताया कि यह अनाज शरीर को पोषण देने और ठीक करने की क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। बड़ी मात्रा में फाइबर, खनिज और प्रोटीन से युक्त, ये अनाज पोषण का एक पावर हाउस हैं। जो प्रचलित जीवनशैली रोगों का इलाज और प्रबंधन कर सकता है जैसे कि मधुमेह, रक्त शर्करा, उच्च रक्तचाप, हाइपरथायरायडिज्म आदि है। भोजन में कोदरा, कंगनी, कुंटकी, स्वंक, हरी कंगनी, ज्वार, बाजरा, रागी और चीना आदि का प्रयोग करना चाहिए। स्वस्थ भोजन बिमारियों को कंट्रोल करता है।

अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया था। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ 20 दिसंबर, 2021 को आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष' के रूप में घोषित किया है। इसे संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव द्वारा अपनाया गया और इसका नेतृत्व भारत ने किया तथा 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। साझेदारी के तहत मोटे अनाज पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और ज्ञान के आदान-प्रदान में भारत को विश्व का नेतृत्व करने में समर्थन दिया जाना है। आशय पत्र के तहत नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच रणनीतिक तथा तकनीकी सहयोग पर ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा, इस साझेदारी का लक्ष्य है छोटी जोत के किसानों के लिये सतत आजीविका के अवसर बनाना, जलवायु परिवर्तन को देखते हुये क्षमताओं को अपनाना और खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना है।

पौष्टिक रूप से संपन्न

- उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लौह तत्व जैसे खनिजों के कारण बाजरा कम खर्चीला और पौष्टिक रूप से गेहूं एवं चावल से बेहतर होता है।
- बाजरा कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। उदाहरण के लिये रागी को सभी खाद्यान्नों में सबसे अधिक कैल्शियम सामग्री के लिये जाना जाता है।
- बाजरा पोषण सुरक्षा प्रदान कर सकता है और विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं में पोषण की कमी के खिलाफ़ एक ढाल के रूप में कार्य कर सकता है।
- इसकी उच्च लौह सामग्री भारत में प्रजनन आयु की महिलाओं तथा शिशुओं में एनीमिया के उच्च प्रसार से लड़ सकती है।

उपज में काफ़ी बेहतर

बाजरा प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है और इस पर जलवायु परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। बाजरा खराब मिट्टी में भी बहुत कम या बिना किसी सहायता के उग सकता है। बाजरा कम पानी की खपत वाला अन्नाज है और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों, सूखे की स्थिति, गैर-सिंचित परिस्थितियों में उत्पादन में सक्षम है। बाजरे की तुलना में चावल के पौधों को बढ़ने के लिये कम-से-कम तीन गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। हरियाणा में बाजरा की पैदावार रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों में अधिक होती है।

क्या कहना है किसानों का

रेवाड़ी के प्रगतिशील किसान विक्की यादव चार एकड़ ज़मीन में जैविक बाजरा की खेती करते हैं। वह खुश है कि हरियाणा सरकार द्वारा 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष' के रूप में घोषित किया गया। उनका कहना है कि वर्तमान समय में लोगों का ध्यान मोटे अनाज की ओर लाने की ज़रूरत है। मोटे अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारी होते हैं। बाजरा सेवन से हमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहती है और यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है।

हरियाणा में क्या होगा ख़ास

- पोषक-अनाज अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- इन फसलों की पौष्टिक महत्ता को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।
- इसके लिए कृषि विभाग में 2023 के लिए विशेष रूप से कार्यशालाओं गोष्ठी, मेले व प्रशिक्षण शिविरों के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी।
- इन फसलों को पी.डी.एस, मिड डे मील व अन्य राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम लोगों की खाद्य आदतों में शामिल किया जाएगा।

बाजरे का समर्थन मूल्य

हरियाणा सरकार ने 2,350 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बाजरे की खरीद करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य यही तय किया है। हरियाणा में यदि 2,350 रुपए प्रति क्विंटल से कम पर बाजरे की बिक्री होती है तो सरकार ने 'भावांतर भरपाई योजना' के तहत 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को प्रदान करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार के दाम के बीच के अंतर को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है।

मोटे अनाज को भोजन में करें शामिल

रेवाड़ी के प्रगतिशील किसान यशपाल खोला ने कहा कि 50-60 वर्ष पहले ज्वार,बाजरा, रागी, मडुआ, कोदो,जौ,चना जैसे मोटे अनाज हमारे प्रमुख भोजन का हिस्सा होते थे। गेहूं, चावल इस्तेमाल हुआ तो वे अनाज दूर होते चले गए। हो सकता है आज की बीमारियों में इस फेरबदल का हाथ हो। उन्होंने कहा मोटे अनाजों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक से पचता है और आसानी से पेट साफ होता है। मोटे अनाज स्वाद मे थोड़े मीठे होते हैं, बिना सब्जी के खा सकते हैं।

मिलेट्स है सुपरफूड

धारुहेड़ा गांव के प्रगतिशील किसान संजय यादव का कहना है कि मिलेट्स सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, मिलेट्स में प्रोटीन, फाइबर, बी विटामिन, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, कॉपर और सेलेनियम सहित बहुत से पोषक तत्व होते हैं। मिलेट्स एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स, एंथोसायनिन, सैपोनिन और लिग्नन्स का एक पावरहाउस भी हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसलिए इन्हें सुपरफूड कहा जाता है। कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के साथ कम उपजाऊ मिट्टी में भी मिलेट्स को उगाया जा सकता है।

मोटे अनाज की खेती बढ़ेगी

कुरुक्षेत्र के प्रगतिशील किसान कुलवीर का कहना है कि 50 साल पहले तक भारत में मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी आदि प्रमुख अनाज थे। लेकिन समय के साथ इनका महत्व खो गया और भारतीयों ने पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर मिलेट्स को मोटे अनाजों और ख़ास तौर पर ग्रामीण खाने के रूप में देखना शुरू कर दिया। अब सरकार 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज' घोषित करके मोटे अनाज के सेवन के लिए प्रेरित कर रही है। इससे लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा।

गांवों की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा गया है कि वे विकास कार्यों पर पूरा ध्यान दें।

हरियाणा सरकार लाभार्थियों को चार रंगों के अलग-अलग राशन कार्डों से मुक्ति दिलाने जा रही है। परिवार पहचान पत्र के वेरिफिकेशन के आधार पर राशन कार्ड बनाए गए हैं।

मेहमान परिंदों से गुलज़ार भिंडावास

मनोज प्रभाकर

झज्जर की भिंडावास झील दूरवर्ती क्षेत्रों से आए मेहमान परिंदों से गुलजार हो गई है। साइबेरिया के ठंडे इलाकों से आए हजारों बहुरंगी पक्षियों ने यहां डेरा जमाया है। सैंकड़ों प्रजातियों के इन पक्षियों का कलरव प्राकृतिक संगीत की अनुभूति कराता है जिसे सुनने व देखने के लिए अनेक पक्षी प्रेमी यहां खिंचे चले आते हैं। अद्भुत सौंदर्य वाले पक्षियों का जल सतह पर कलाबाजियां खाना, जलक्रिड़ा करना और अटखेलियां करना मनभावन होता है।

विभागीय जानकारी के मुताबिक इस बार 40 हजार से ज्यादा पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां पहुंचे हैं। ग्रेलेग गूज़ व स्पॉट बिल डक की संख्या ज्यादा है। इस बार इनके साथ पेरेग्रिन फॉल्कॉन भी हैं। इन पक्षियों की उड़ान व क्रियाकलाप सबसे तेज मानी जाती है। ये सभी विदेशी मेहमान इस क्षेत्र में अक्टूबर से फरवरी तक रहन सहन करते हैं। उसके बाद वापस अपने देशों को लौट जाते हैं। इन चार पांच माह के दौरान यहां का ठंडा मौसम इन पक्षियों के लिए अनुकूल रहता है। इस दौरान इनके अपने क्षेत्र में ज्यादा ठंड होती है। ज्यादा ठंड होने से अधिकांश जमीन पर बर्फ जम जाती है जिससे खाने का संकट हो जाता है। खाने की तलाश में ये पक्षी हरियाणा-पंजाब के कई जलीय इलाकों में चले आते हैं।

भिंडावास झील के अलावा यहां के गांव डीघल व मांडोठी की सैंकड़ों एकड़ जमीन पर बने पोखर भी इन पक्षियों की मेजबानी करते हैं। सर्दियों से पहले बरसात के मौसम में यहां के दर्जनों जोहड़ तालाब पर्याप्त जलयुक्त हो जाते हैं। जहां इन्हें खाने के लिए छोटे-छोटे जलजीव मिल जाते हैं और आराम करने के लिए पेड़ व झाड़ियां।

सहजभावयुक्त दिखने वाले ये पक्षी संवेदनशील और तेज दिमाग के होते हैं। हर साल ये अपने उन्हीं निर्धारित स्थानों में चले आते हैं, जहां बीते वर्ष आकर रह चुके होते हैं। इतने दूर से आने के बावजूद ये भटकते नहीं हैं। यहां से जब ये अपने घर लौटते हैं, तब वहीं अंडे देते हैं।

गज़ब का दिशा ज्ञान

जीव जंतु संरक्षण से संबंद्ध संस्था के सदस्य सोनू दलाल ने बताया कि ये पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां तक पहुंचते हैं। इनका दिशा ज्ञान गज़ब का होता है। रास्ते में ये पक्षी सूर्य व तारों की मदद लेते

हैं। उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ते रहते हैं। राह में नदी, पर्वत व झीलों की लोकेशन की भी मदद लेते हैं। अपने देशों में बर्फ जमने से पूर्व ये पर्याप्त वसा अपने शरीर में जमा कर लेते हैं और फिर उड़ान भरते हैं।

यह वसा इनकी मुख्य ऊर्जा है, जिसे एकत्र कर लेने के बाद यात्रा प्रारंभ होती है। परिपूर्ण होकर यात्रा शुरू करते हैं तो इन्हें रास्ते में कहीं भोजन की जरुरत नहीं पड़ती। ऐसा ही ये परिंदे तब करते हैं जब यहां से स्वदेश की ओर यात्रा भरते हैं। शरीर में पर्याप्त वसा एकत्र करके चलते हैं। प्रवास के दौरान ये पक्षी उत्तर से दक्षिण की ओर उड़ान भरते हैं। ये पक्षी अक्सर आसमान में अंग्रेजी के अक्षर 'वी' आकार की आकृति बनाकर चलते हैं। इस तकनीक से इनकी ऊर्जा में बचत होती है।

300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

विदेशी धरा से यहां पहुंचने वाले पक्षियों की खास विशेषता इनके उडने की क्षमता होती है। कुछ पक्षी तेज उड़ान भरते हैं, तो कुछ बिना रुके लगातार लंबी उड़ान भर सकते हैं। ये दो अलग-अलग गुण हैं, जो हर पक्षी में नहीं होते, लेकिन पक्षी पेरेग्रीन फॉल्कॉन में ये दोनों ही विशेषताएं होती हैं। आकार में छोटा सा दिखने वाला यह पक्षी कुछ ही हफ्तों में हजारों किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। उसे विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी भी कहा जा सकता है। इसे अपना आहार जुटाने के लिए शिकार पकड़ना होता है तो इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होती है।

साइबेरियन पक्षियों का मेला

वन्यजीव विभाग, भिंडावास झील के स्थानीय अधिकारी राजेश ने बताया कि साइबेरियन देशों से आने वाले पक्षियों की सैंकड़ों प्रजातियां हैं। इनमें मार्श रेसिपीपर, आम रेत कीपिंग, ग्रीन रेडपीपर, सामान्य स्कूप्स, सामान्य रेडशैंक, स्पॉटेड रेडशैंक, जल-कपोत ग्रेलेग गुज़, उत्तरी शावलर, फेर्रुजनीस पोचर्ड, टिमिनिक कार्यकाल, छोटा कार्य पिच्छर एवोकेट, मार्श हैरियर आम टीला, व्हाइट आइबिल, पेंटिड स्ट्रॉक, स्कूनबिल, नॉर्दन सोलर, मलाइड, फ्लेमिंगो, पेंटल आदि पक्षी हैं।

सुलतानपुर और भिंडावास की है अंतरराष्ट्रीय पहचान

गुरुग्राम जिले में सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा झज्जर जिले में भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की आर्द्रभूमि को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है।

शीतकालीन मौसम में ये दोनों क्षेत्र विदेशी पक्षियों के लिए आरामगाह साबित होते हैं। पक्षियों को यहां न केवल सुरक्षित स्थल मयस्सर होता है बल्कि मछलियों के रूप में भरपूर भोजन भी मिलता है। जानकारी के मुताबिक यहां हर वर्ष 100 से अधिक प्रजातियों के लगभग 50,000 प्रवासी पक्षी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आते हैं।

सुल्तानपुर में प्रवासी पक्षियों की चहचाहट एक सुरम्य चित्रमाला सरीखी उपलब्ध करवाने का काम करती है जिसमें सारस क्रेन, डेमोइसेल क्रेन, उत्तरी पिंटेल, उत्तरी फावड़ा, रेड-क्रस्टेड पोचार्ड, वेडर, ग्रे लैग गूज़, गडवाल, यूरेशियन विजन, ब्लैक-टेल्ड गॉडविट आदि पक्षी शामिल होते हैं। सुलतानपुर कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के निवासी पक्षियों का भी स्थल है। धान के ग्रे फ्रेंकोलिन, ब्लैक फ्रेंकोलिन, इंडियन रोलर, रेड-वेंटेड बुलबुल, रोज-रिंगेड पैराकेट, शिकारा, यूरेशियन कॉलर डव, लाफिंग डव, स्पॉटेड ओवलेट, रॉक पिजन, मैगपाई रॉबिन, ग्रेटर कौकल, वीवर बर्ड, बैंक मैना, कॉमन मैना और एशियन ग्रीन बी-ईटर आदि पक्षी सुलतानपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं।

भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य मीठे पानी की आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा स्थल है। सर्दियों के दौरान 80 प्रजातियों के 40 हजार से अधिक पक्षी भिंडावास में प्रवास के लिए आते हैं। भिंडावास क्षेत्र में सफेदा और बबुल के ऊंचे पेड़ हैं जो ओरिएंटल हनी-बजई, पाइड किंगफिशर आदि पक्षियों के लिए बहुत अच्छा प्रवास प्रदान करते हैं।

हरियाणा सरकार की ओर से सुलतानपुर और भिंडावास को छोटा आइसलैंड बनाने के लिए आर्द्रभूमि में कई विकास कार्य कराए गए हैं। झीलों से लंबी घास निकाली गई हैं और छोटे द्वीपों की बसासत पक्षियों के अनुकूल की गई है। इस क्षेत्र में पक्षियों के लिए लुभावने फाईकस और कीकर जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनस्पति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा लंबे नीलगिरी के पेड़ मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। इन आर्द्रभूमियों में पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। सुलतानपुर झील में सारस सहित कई पक्षियों ने प्रजनन शुरू कर दिया है।

रामसर सम्मेलन से मान्यता

रामसर ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर के पास एक तटीय शहर है। यह आर्द्रभूमि जल विज्ञान चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पर्यावरण को शुद्ध करते हुए प्रकृति की गोद के रूप में जाना जाता है। प्रवासी जलपक्षियों के लिए आर्द्रभूमि में आवास के नुकसान और गिरावट को ध्यान में रखते हुए रामसर शहर में 1971 में सम्मेलन हुआ था। इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए आर्द्रभूमि पर सन 1975 में एक संधि लागू हुई। यह संधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए मजबूत ढांचा प्रदान करती है।

रामसर कन्वेंशन के दौरान दुर्लभ और अद्वितीय आर्द्रभूमि स्थलों को नामित किया गया है जो जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। बताया गया कि एक बार इन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की कन्वेंशन की सूची में जोड़ा जाये तो इन्हें रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। 'रामसर' एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टैग है, जो आर्द्रभूमि को उसके पारिस्थितिक महत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान करता है। इस प्रकार हरियाणा की आर्द्रभूमि पहली बार विश्व स्थल के पटल पर आई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अलावा, रामसर टैग को पर्यावरण-पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करेगा क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र या उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिये किसी भी खतरे का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी होगी। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन का भी विषय बन जाएगा।

इनके अलावा पेलीसिन, रोजी पेलीसन, कॉमन 'क्रेन, डेमार सेल, बारहेडिड गूज, परपर्ल हॉर्न, नेकस्टॉर्क, पेंटेड स्टॉर्क, ह्वाइट नेक, ग्रे पेल्सिन, पिनटेल डक, शोवलर, डक, कॉमनटील, डेल चिक, मेलर्ड, पोचार्ड, गारगेनी टेल, फ्लेमिंगो सहित कई प्रजाति के पक्षी भी आते रहे हैं। साइबेरिया, ब्रिटेन, मंगोलिया, मध्य एशिया से हजारों की संख्या में विदेशी परिंदे मध्यभारत के मैदानों में आते हैं।

हिसार में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 9,45 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा अध्यापकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 'परीक्षा पे चर्चा-2023' में हिस्सा लेने का आह्वान किया है।

शहरी क्षेत्र के विकास का कॉरीडोर

प्रॉपर्टी आईडी बनने से हुए अनेक समाधान

संवाद ब्यूरो

प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी बनने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। पहले केवल 25 प्रतिशत व्यक्ति ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते थे, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी बन जाने से ये सभी व्यक्ति शहरी स्थानीय निकाय विभाग को प्रॉपर्टी टैक्स देंगे और इससे निकायों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में शहरी क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों की मैपिंग व सर्वे करके 42 लाख 70 हजार से अधिक को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए चिह्नित किया गया है तथा इनकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।

पूरा ब्याज माफ़ किया

हरियाणा सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में 'हाऊस टैक्स ब्याज माफ़ी योजना' के तहत संपत्ति मालिक या किरायेदार को 31 दिसंबर, 2022 से पहले सभी देय संपत्ति कर जमा करवा कर योजना का पूरा लाभ उठाने का अवसर दिया गया। इस योजना के तहत देय हाऊस टैक्स राशि पर पूरा ब्याज माफ़ किया गया। सर्वे के बाद लगभग 12 लाख से अधिक नई सम्पत्तियों की पहचान की गई। अभी तक 1 लाख 98 हजार आपत्तियां दर्ज़ हुई है। इनमें से एक लाख 60 हजार आपत्तियों का निपटान किया जा चुका है तथा शेष 38 हजार आपत्तियों के निपटान का कार्य प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

'मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना' के तहत शहरी क्षेत्रों में 20 साल से अधिक मकानों व दुकानों के किराएदारों को मालिकाना हक देने के लिए 7077 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1761 को मालिकाना हक दिया गया है तथा 1304 आवेदन रद्द हुए और 4012 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में ई-नीलामी प्रक्रिया के तहत विज्ञापन नीति क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत अब तक 342 साईटों को चिह्नित किया गया है तथा जिनमें से 42 साईट की ई-नीलामी हुई है जिससे 5.92 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी हुई है। यह आय निकायों में विकास कार्यों पर खर्च की जानी है।

अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित

राज्य के विभिन्न शहरों में विकसित अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जारी है। सर्वे के दौरान 2,237 कॉलोनियां अवैध मिली हैं। इनमें शहरी निकायों के द्वारा 1,409 कॉलोनियों को नियमित करने हेतु प्रस्ताव पारित किये गये हैं। सरकार ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवेदन मांगे है। आर.डब्लू.ए. के माध्यम से अब तक 46 कॉलोनियों के आवेदन के प्रस्ताव मिले हैं। इन कॉलोनियों को लागू नियमानुसार जल्द ही नियमित किया जाएगा।

स्वच्छ शहर-सुरक्षित शहर

सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्रदेश में 101 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट का निष्पादन किया जाना था, इसमें से 40 लाख मीट्रिक टन कूड़े का निष्पादन किया जा चुका है। शेष कूड़े का भी जल्द ही समाधान किया जाएगा। डोर टू डोर कूड़े को एकत्र करने के लिए प्रदेश में 13 क्लस्टर बनाए गए हैं। इनके तहत सोनीपत व पानीपत में 700 मीट्रिक टन क्षमता का एक कचरा प्रबंधन प्लांट संचालित है। गुरुग्राम व फरीदाबाद में 1500 मीट्रिक टन क्षमता का प्लांट शीघ्र लगा दिया जाएगा। इसके अलावा, करनाल-कैथल-थानेसर में 638 एमटी, सिरसा में 168 एमटी व भिवानी में 155 एमटी क्षमता के ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट लगाए जा रहे हैं। अंबाला-यमुनानगर, रोहतक-बहादुरगढ-झज्जर, हिसार-फतेहाबाद, जीन्द, रेवाड़ी, पलवल-पुन्हाना, फरूखनगर व पंचकूला में शीघ्र ही कचरा प्रबंधन प्लांट लगाए जाएंगे।

पोर्टल पर रख सकते हैं अपनी बात

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि 'नगर दर्शन पोर्टल' के माध्यम से कोई भी शहरी क्षेत्र का नागरिक अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए इस पोर्टल पर अपनी मांग भेज सकता हैं। उनकी मांगों को जनप्रतिनिधियों द्वारा सत्यापन करने के बाद निवारण किया जा रहा है। इसी प्रकार हरियाणा इंजीनियरिंग वर्कस पोर्टल भी संचालित किया जा रहा है जिस पर शहरी स्थानीय निकाय, एच.एस.आई.आई.डी.सी., एच.एस.वी.पी. व लोक निर्माण विभागों आदि से संबंधित विकास कार्यों को करवाने हेतु इंद्राज करवाए जाते है तथा इन विकास कार्यों की मोनिटरिंग व अदायगी भी इस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। अब तक कुल 8,798 विकास कार्य करवाने के अनुमान इस पोर्टल पर दर्ज हुए हैं, जिनमें से 3,402 अकेले शहरी स्थानीय निकाय विभाग के हैं।

दूसरे राज्यों के लिए मॉडल बना हरियाणा

हरियाणा सरकार की योजनाएं दूसरे राज्यों में भी लोकप्रिय हो रही हैं। बहुत सी योजनाओं को दूसरे प्रदेशों ने भी अपनी व्यवस्था में शामिल किया है।

सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ कम से कम मानव हस्तक्षेप के सीधे लोगों को मिले इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी पहल करते हुए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) की एक अनोखी योजना आरंभ की है जो शायद देश के किसी राज्य में नहीं है। परिवार के हर सदस्य का सटीक सत्यापित डाटा परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध है। उत्तराखंड राज्य पहले ही हरियाणा की तर्ज़ पर परिवार पहचान पत्र बनाने की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर चुका है। अब जम्मू-कश्मीर ने भी इस योजना को अपनाने की पहल की है। इससे पूर्व भी हरियाणा की अध्यापक स्थानांतरण नीति का छह राज्यों ने अध्ययन किया था और अब परिवार पहचान पत्र की योजना का अध्यनन महाराष्ट्र व उत्तराखंड राज्यों ने किया है। जम्मू-कश्मीर में हर परिवार को यूनिक आईडी 'जेके फैमिली आईडी' देने की पहल शुरू हुई है।

अंत्योदय भाव के साथ पिछले आठ वर्षों से घर-द्वार पर ही लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ की गई व्यवस्था परिवर्तन की ऑनलाइन प्रणाली के परिणाम ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल से हरियाणा सही मायनों में देश के समक्ष अंत्योदय का रोल मॉडल बनकर उभरा है और इस कड़ी में परिवार पहचान पत्र एक अहम दस्तावेज़ बना है।

भारतीय नागरिकों की विशिष्ट पहचान के लिए केंद्र सरकार ने 12 अंकों के आधार कार्ड को अहम दस्तावेज़ बनाया है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में अलग से नागरिक संसाधन सूचना विभाग सृजित कर आठ अंकों का परिवार पहचान पत्र बनाया है जिसमें परिवार के हर सदस्य की एक-एक जानकारी उपलब्ध है। आठ अंकों में तीन नंबर अंग्रेजी वर्णमला के हैं जबकि आधार में सभी नंबर गणित संख्यात्मक हैं। उत्तराखंड ने परिवार पहचान पत्र को 14 अंकों का बनवाने का निर्णय लिया है और यह कार्य नियोजन विभाग को सौंपा है।

सीएम विंडो और ऑनलाइन स्थानांतरण

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 दिसंबर, 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सुशासन की पहल करते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की थी। जिसके तहत सभी जिलों के लघु सचिवालय में सीएम विंडो के काउंटर खोले गए। बाद में उपमंडल स्तर पर भी काउंटर खोले गए जिसका आलम यह हुआ कि प्रदेश के लगभग 10 लाख 33 हजार से अधिक लोगों ने चंडीगढ़ आये बिना ही सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई और इस व्यवस्था के माध्यम से 9 लाख 44 हजार से अधिक शिकायतों, समस्याओं, सुझावों व मांगों का समाधान घर बैठे ही संभव हो पाया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में एकाएक ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति लागू कर एक ही क्लिक से 75,000 से अधिक अध्यापकों का एक साथ स्थानांतरण करके देश भर में तहलका मचा दिया।

सीएम विंडो की तर्ज़ पर अब मुख्यमंत्री ने एक और पहल करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अलग से प्रकोष्ठ बनाने का निर्णय लिया है जिसमें क्लास-1 श्रेणी के अधिकारियों द्वारा 'ग्राम सरंक्षण योजना' के तहत गोद लिए गए गांवों में हो रहे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग व फीडबैक ली जाएगी जिसका विश्लेषण स्वयं मुख्यमंत्री अपने डैशबोर्ड पर करेंगे। यह एक नई पहल होगी।

पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण प्रदूषण को मुख्यमंत्री ने मानवता के लिए चुनौती माना है और पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानकर योजनाएं बनाने पर ज़ोर दिया है। इसके लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों को योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल की एनजीटी के चेयरमैन ने भी सराहना की है। इसी प्रकार कोरोना काल के दौरान स्वयं मुख्यमंत्री ने जल सरंक्षण की 'मेरा पानी मेरी विरासत' के नाम से एक नई योजना तैयार की। जिसके तहत अब हरियाणा में धान की जगह कम पानी से तैयार होने वाली अन्य फसल बोने वाले किसानों को 7 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा एसटीपी के उपचारित पानी का पुनः उपयोग हो, इसके लिए भी हरियाणा में योजनाएं बनाई जा रही हैं। किसान पराली अपने खेतों में न जलाये इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने पराली की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हो, इस दिशा में भी केंद्र सरकार से मांग की है।

-संवाद ब्यूरो

परिवार पहचान पत्र

परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य राज्य में रह रहे परिवारों के लिए एक व्यापक, विश्वसनीय तथा सटीक डाटाबेस तैयार करना है। कोई भी परिवार जो वर्तमान में हरियाणा में रह रहा है, उसको परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। स्थाई रूप से रहने वाले परिवारों को 8 अंकों का पीपीपी जारी किया जायेगा। इसी प्रकार कोई परिवार हरियाणा से बाहर रह रहा है परंतु राज्य की किसी सेवा या स्कीम के लिए आवेदन कर रहा है उसको भी पीपीपी में पंजीकरण करना होगा। ऐसे परिवारों को 9 अंकों का अस्थाई परिवार पहचान जारी की जाएगी जिसके ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ' अंकित होगा।

आवेदन के लिए किसी अंत्योदय केंद्र, नागरिक सेवा केंद्र, ऑनलाइन वेबसाइट (meraparivar.haryana.gov.in) या पीपीपी ऑपरेटर पूरे राज्य में पीपीपी कार्य के लिए पंजीकृत ऑपरेटरों में से कोई पीपीपी ऑपरेटर से संपर्क करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि दूर करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त या जिला नागरिक संसाधन सूचना प्रबंधक से संपर्क करें।

भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन आगामी 2 फरवरी से 9 फरवरी 2023 तक ओलंपिक श्री बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम सेक्टर- 3 एसएस नगर मोहाली में किया जाएगा।

हरियाणा में 'विलेज ऑफ एक्सीलेंस' के माध्यम से बेहतर कृषि, बागवानी व पशुपालन में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज़ करने वाले गावों को चिह्नित किया जा रहा है।

हरियाणवी बोली और लोक साहित्य

'हरियाणवी' शब्द का स्पष्ट संकेत हरियाणा की बोली से है इसकी कई उप-बोलियां हैं, जैसे- मेवाती, अहीरी या आभीरी, बागड़ी, अंबालवी, कौरवी, पहाड़ी आदि। डॉ जयनारायण कौशिक अपने हरियाणवी हिन्दी कोश की भूमिका में लिखते हैं- अहीरी, मेवाती, बागड़ी, कौरवी के परनाले बरसाती नालों के समान कहीं-कहीं अपनी सत्ता को स्पष्ट दर्शाते दीख पड़ते हैं लेकिन घूम-फिर के अपने उद्गम स्रोत हरियाणवी में ही पुनः विलीन हो जाते हैं। उक्त समस्त उपबोलियों के पुंज का नाम हरियाणवी है।

1961 की नयी जनगणना के उपरान्त एक नयी चेतना ने जन्म लिया, इस चेतना के परिणामस्वरूप भाषाई चेतना जागी। फलतः 1966 में भाषायी आधार पर हरियाणा का जन्म हुआ। इसकी सीमाएं निश्चित की गईं। विद्वानों ने प्रदेश की भाषा को विभिन्न नामों से अभिहित किया। प्रदेश की बोली का नाम सबसे पहले डॉ. गियर्सन ने सर्वे ऑफ इंडिया में बांगरू दिया। हरदेव बाहरी ने इसे अहीरों की भाषा भी माना है। डॉ. नानक चन्द शर्मा, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉ. शंकर लाल यादव सरीखे विद्वानों ने प्रदेश की बोली को हरियाणवी माना। हरियाणवी का दूसरा नाम 'बांगरू' भी माना जाता है। बांगरू में इस प्रदेश की सभी उपबोलियों का कहीं प्रचुर और कहीं आंशिक रूप में समावेश अवश्य है। इसे यहां के 70 प्रतिशत लोग बोलते

सीमा क्षेत्र की दृष्टि से 'बांगरू' रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार के पूर्वी भाग, करनाल, कुरुक्षेत्र ज़िले का दक्षिणी भाग, भिवानी ज़िले के पूर्वोत्तर भाग, झज्जर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ तहसील के कुछ भागों में बोली जाती है। डॉ. जय नारायण कौशिक ने लिखा है- यदि दिल्ली को हरियाणवी का केन्द्र मानकर चलें तो इसमें वे स्थान आते हैं, जो यमुना नदी से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नहरों से सिंचित हैं। यमुना नदी ताजेवाला से पहली बार मैदानी भाग पर अवतरित होती है। वर्तमान हरियाणा वहीं से आरम्भ होता है। इधर पश्चिमी यमुना नहर वर्तमान हरियाणा के करनाल, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रोहतक, गुरुग्राम आदि क्षेत्रों को सींचती है। इस क्षेत्र में बाँगरू, अहीरी, बागड़ी, मेवाती, अम्बालवी आदि उप-बोलियां बोली जाती हैं।' इस सम्पूर्ण क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियों में भी केवल स्थानीय एवं सीमावर्ती प्रभावों को छोड़कर एकरूपता है। केवल उच्चारण भेद दिखाई पड़ता है फिर भी व्याकरण और शब्दावली सारे क्षेत्र में समान है। इस सारे क्षेत्र की भाषा को बाँगरू कहा जा सकता है। उपबोलियों की बानगी देखिये ...

हरियाणवी के कई शब्द कोश उपलब्ध हैं, डॉ. जयनारायण कौशिक का हरियाणवी-हिन्दी कोश, डॉ. हरदेव बाहरी का हरियाणवी शब्द कोश, डॉ. हरद्वारी लाल शर्मा का कौरवी बोली का शब्द कोश आदि-आदि।

हरियाणवी की भाषागत विशेषताएं

'ण' हरियाणवी की प्रिय ध्वनि है। तालव्य 'श' और मूर्धन्य 'ष' का सर्वथा अभाव है, इनके स्थान पर दन्त्य 'स' की ध्वनि उच्चरित होती है। 'औ' के स्थान पर 'ओ' की ध्वनि उच्चरित होती है। 'है' को 'सै' बोला जाता है।

यदि हरियाणवी की हिन्दी से तुलना करें तो हमें ज्ञात होता है कि इस भाषा में स्वर और व्यंजन सम्बंधी कई भेदोपभेद मिलते हैं-'अ' की ध्वनि हरियाणवी में कहीं 'आ' हो जाती है,

जैसे- अगला-आगला, ककड़ी-काकड़ी। कहीं 'अ' का लोप, जैसे- अमावस-मावस, अहीर-हीर।

'आ' की ध्वनि कहीं 'अ' जैसे- आसमान-असमान। कहीं 'आ' ध्वनि 'ओ' में परिवर्तित हुई है, जैसे- गया-गयो।

'ओ' का प्रभाव विशेषतः अहीरी और बागड़ी उपबोली में मिलता है। सभी स्वरों में न्यूनाधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं।

इसी प्रकार व्यंजनों की ध्वनियों में भी परिवर्तन मिलता है। हरियाणवी में अपने प्रत्यय हैं, जैसे- आणा-समधी-समधाणा, पीतल-पितलाणा आदि ओहड़ा प्रत्यय, जैसे- बास्सी-बासोहड़ा इत्यादि।

हरियाणवी में वैदिक संस्कृत के शब्दों का विपुल भण्डार है। यथा-आरणी (वैदिक संस्कृत)- आरणी या आरणा (हरियाणवी) इसी प्रकार- आल-आल (कच्चा प्याज), जनी-जनी या जणी (स्त्रियों का समूह) तद्भव या सादृश्य शब्द- जैसे- अजगर-ईजगर, अर्गल-अरली, ईर्ष्या-ईरखा, उत्त्म्भन-उलाळ्वा करीष-करसी, ग्रामि-गामोल्ली, घर्म-घाम, दर्भ-डाभ आदि

लौकिक संस्कृत और हरियाणवी के तुल्य शब्द

अंबर, कुरंड, चीर, चूड़ा, दया, मण, रण, रस, रूप सार आदि अनेक शब्द ज्यों के त्यों दोनों में समान हैं।

संस्कृत के तद्भव शब्द भी अवधेय है, जैसे- अवसर-ओसरा, करील-कैर, खंड-खण, घटमंच-घड़ोंच्ची (मटका रखने का मंच) चूड़ा चूंड्डा, दर्भमंच-डामचा, प्रतोलिका-पौळी, मनुष्य-माणस, लप्सिका्-लापसी आदि-आदि।

हरियाणवी शब्दावली का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, मगधी, अर्धमगधी अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, स्पेनिश, जर्मनी आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे जो इसे विशेष स्थान दिलाने में सहायक हैं। जैसा सर्वविदित है कि भाषा पहले बनी और व्याकरण बाद में। हरियाणवी के शब्दों को भी व्याकरण द्वारा अनुशासित करने की महती आवश्यकता आन पड़ी है ताकि हरियाणवी बोली भाषा का रूप धारण कर सके।

हरियाणवी रचित साहित्य में लगभग सभी विधाओं की रचना हुई हैं । कविता, राग, रागनियां, नाटक, रेडियो नाटक व झलकियां, उपन्यास, कहानी, निबन्ध, लघुकथा, लघुकविता, हाइकु आदि विभिन्न विधाओं पर हरियाणवी लेखकों ने खूब कलम चलाई है।

आजकल प्रदेश के अनेक कवि हरियाणवी में काव्य रचना सोत्साह कर रहे हैं। हरियाणवी साहित्य में सांग विधा लोक जीवन में सर्वाधिक प्रिय रही है। सूर्यकवि पं. लखमीचन्द सहित पं. मांगेराम, बाजे भगत, धनपत सिंह, रामकिशन व्यास, माईचन्द, तुलाराम, सुलतान, जयनारायण आदि हरियाणा के चर्चित सांगी रहे हैं। चौ. प्रतापसिंह द्वारा लिखित रेडियो नाटक 'ताउ झगड़ू' ने तो हरियाणा के लोकजीवन में खूब वाहवाही लूटी ।

हरियाणवी में बहुत कम उपन्यासों की रचना हुई है। श्री राजाराम शास्त्री द्वारा रचित 'झाड़ूफिरी' को हरियाणवी का प्रथम उपन्यास होने का श्रेय प्राप्त है। डॉ. श्याम सखा श्याम का 'समझणिए की मर' डॉ. जगबीर राठी का 'युद्धवीर' और डॉ. प्रदीप नील का 'कहवै जाट सुण जाटणी' भी उल्लेखनीय उपन्यास है।

-डॉ. जयभगवान शर्मा

सुण छबीले बोल रसीले

म्हारा गांव सुथरा गांव

एक बै एक बूढ़ा नहाकै, नए कपड़े पहरकै और हाथ में डोगा लेकै घर तैं चालण की तैयारी में था। उसनै देखकै उसकी पोती बोली- दादा कितोड़ जा सै?

दादा बोल्या- बेटा, बाहर जा सूं, तेरी खातर कितै घर- बार देखण।

छोरी बोली- आच्छा दादा, ठीक सै। कोय इसी जगहां देखकै आइये जड़ै गाम की खुली-खुली गाल हों

घर थोड़ा-सा बडा और हवादार हो, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो, आंगन में पेड़ पौधे हों, गलियां में कितोड़ किचड़ ना हो, साफ सफाई वाली हों, मतलब घरां के निकासी के पानी का ठीक बंदोबस्त हो। घर की जिड़ में कोई छोटा -मोटा पार्क हो तो बढ़िया रहगा।

दादा बोल्या- बेटी जै इसा बढ़िया घर पा ज्यागा, तो उड़ै मैं ए ना रहल्यूंगा।

छोरी आपणे दादा के मुहं कान्या देखती रहगी।

- रसीले ये सारी सुख सुविधा कित पावैं सैं। घर पा ज्या सै तो बर नहीं, और बर पाज्या सै तो घर नहीं। इनकी भी देखी जा। अड़ौसी पड़ौसी तो कोनी देखे जाते। वे ठीक होंगे तो ठीक और गलत होंगे तो भी ठीक। वे तो बदले ना जां। गाम में और शहर में फर्क सै। शहर में तो किसे अड़ौसी नै पड़ौसी तैं कोए मतलब ना होता। पर गाम में अड़ौसी भी चाहिए और पड़ौसी भी चाहिए।

- छबीले भाई मिल जुलकै रहण में ए स्वाद सै। एकला रहणा हो तो जंगलां में जाकै रहले। हिमालय परबत पै चले जां जड़ै ऋषि मुनि रहै सैं। उननै किसे तैं कोए मतलब नहीं।

- पर असल जीवन वोए हो सै रसीले, परिवार में रहते रहते साफ-सुथरा जीवन जीया जा।

- हां भाई, बहुत से भाई इसे भी सैं जिनकी पूरी उम्र एंड में लिकड़ज्या सै। पर किसे गैल्यां सौले माथे बात ना करैं। ऊपर तैं न्यू और दिमाग में राखैंगे अक सारी दुनिया उसतै राम राम करै, औ वो किसे त ना करै। खुद का ब्यौंत चाहे दो आन्ने का ना हो, पर नमस्ते चाहिए मण-मण की।

- हां, वे आपणे आपे नै बडा ज्ञानी भी मानैं सैं। नहांए चाहे म्हीने हो ज्याते हों।

- हां भाई मैं तो तीसरे दिन न्हा ल्यूं सूं। जाड्डा में पहल्यां रोज नहा लिया करता। उस वक्त बिजली की चोरी हो जाया करती, पर जिब तैं यो सरकार बणी सै, चोरी कोन्या होती।

- भाई चोरी करण की जरुरत भी कोन्या। सरकार नै रेट इतणे कम कर राखे सैं अक इतणे में कोए हलवी भारा कोन्या होती। यो तो मन के बहम सैं अक घणा बिल आवैगा तो नुकसान होज्यागा। ना तो घणा बिल आता और ना नुकसान होता। चोर की फीत भी कोन्या लागती।

- भाई सही बात तो यो सै अक इस सरकार में चोरी करण तैं आत्मा भी कोन्या मानती। सीएम इतणा ईमानदार सै अक उसकी गेल्यां दगा करणा भगवान को दगा करणे के समान सै। जो हेराफेरी करैं सैं उननै इसै जन्म में चुकता करणा पड़ैगा।

-रसीले जिस गाम की गली तंग सैं और उनमें ढंग तै घरां के निकासी के पानी की ठीक व्यवस्था नहीं सै, उड़ै अड़ोसी-पड़ौसी का जूत देर सबेर बाजे जा सै। गामां में ईब नई पंचायत बणगी सैं उननै इस ओर ध्यान देणा चाहिए।

- देख छबीले यो समस्या आपणे गाम में भी सै। इस समस्या का समाधान तो हम सबनै मिल बैठकै करणा पड़ैगा। इसमें सरकार के करैगी। हाम करैंगे और पंचायत करैगी। रौळा करे तैं कोए काम सुधरा नहीं करता, बिगड़या करै।

-रसीले, मरोड़ कै तो करोड़ लाग्या करैं। गली में उरेन-परेन गंदगी फैलैगी तो बीमारी फैलैगी। बीमार होगे तो डाक्टर कै जाणा पड़ैगा। खर्चा होगा, बीरानमाटी होगी। इसतै आच्छा सारे मिल-बैठकै समस्या का समाधान करैं तो ठीक रहैगा। गाम राम में हर समस्या का समाधान हो सै।

-छबीले सरकार भी कहै सै अक पीस्से की कमी कोन्या, काम करवाणे आले होणे चाहिंए। तो सरकार की मदद ली जावैगी।

-भाई घरां बैठे कोए न्यू कोन्या पूछण आवै अक थाम राजी सो अक नाराज सो। हाथ पां हिलाये तैं और घर तैं बाहर जाए तैं काम होया करैं। न्यू भी कहा करैं काम छोड़् काम हो सैं। पर दुर्भाग्य तो यू सै रसीले लोग न्यू चाहवैं सैं अक बिना कुछ हाथ पां हिलाए सरकार ए सारे काम कर दे। और वे सारा दिन ताश पीटे जां। चाल चालैंगे, काल कर्या सो आज कर।

- छबीले, गाम में नई पंचायत बणगी सैं। पढ़ी लिखी पंचायत सैं, हर बात नै समझैं सैं। उनको हौंसला देणे की जरुरत सै। काम करैंगे। सारे गाम आल्यां नै उनका सहयोग करणा चाहिए। ईबकै इसा काम करणा चाहिए अक दूसरे गाम आळे भी आकै देखकैं अक इतणा साफ सुथरा गाम क्यूकर सै। पूरे गांव में सफाई का विशेष ध्यान राखैंगे। पार्क बणावैंगे, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी, मंदिर और ग्राम सचिवालय की देखरेख करैंगे। गांव के चौगरदे कै सीसीटीवी कैमरे लगवाए जांगे ताकि सुरक्षा के इंतजाम बढ़िया हो सकैं।

-रसीले, इतणे काम होज्यांगे तो ग्राम पंचायत सरकार तैं ईनाम लेण की हकदार होज्यांगी। विकास खातर और बजट मिलज्यागा तो और काम होंगे।

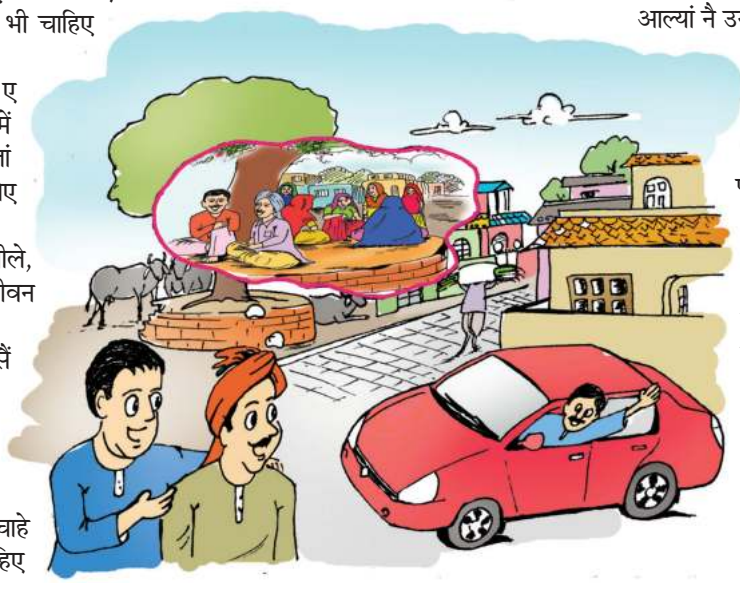

-मनोज प्रभाकर

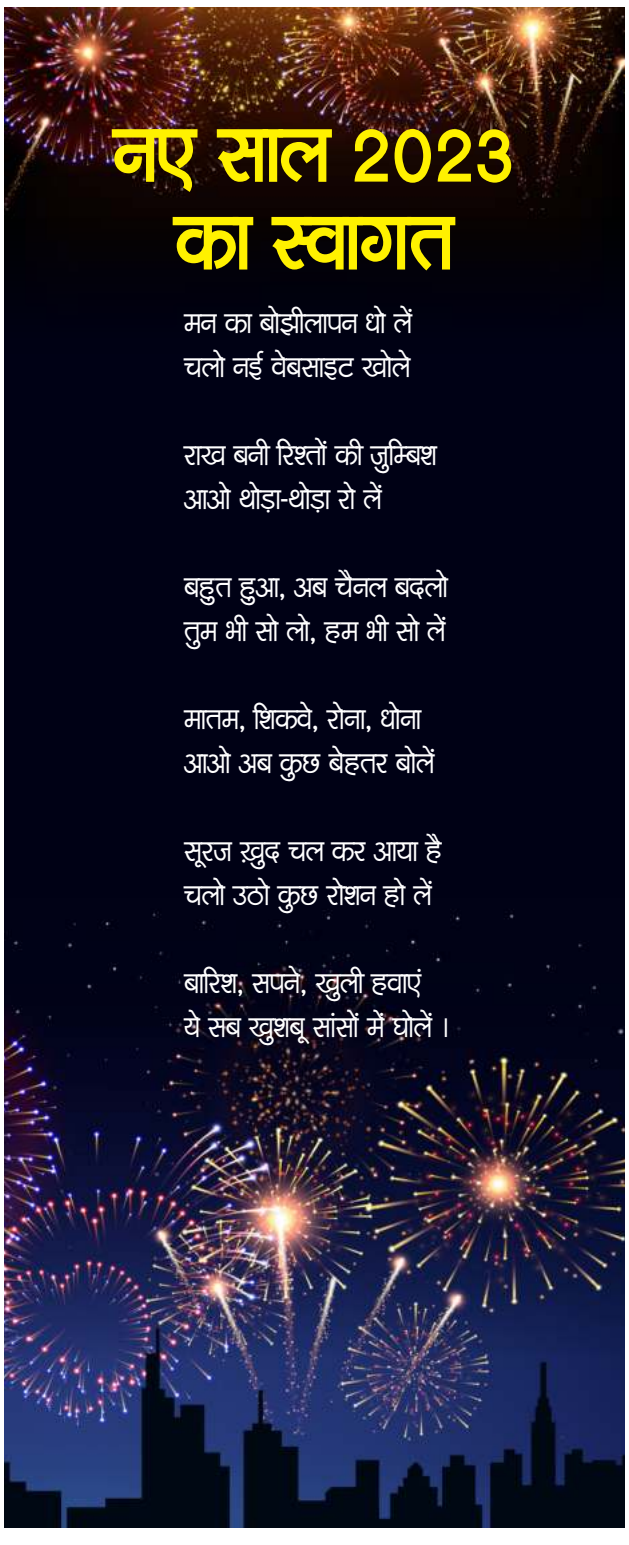

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com